RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

विजयदशमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 7 OCTOBER TO 13 OCTOBER 2019 • VOLUME-9 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

लोगों को गुमराह करना बंद करे सरकारी अफसर

नैशनल हाईवे विभाग

लोगों की जान की कीमत को समझें एन.एच.ए.आई विभाग

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

जालंधर ब्रीज द्वारा प्रकाशित खबर जिसमें कि उसने नैशनल हाईवे पर खड़े पानी की समस्या, आस-पास हुए अवैध कब्जे और बंद पड़ा पी.ए.पी फ्लाई ओवर और निर्माणधीन रामामंडी फ्लाई ओवर जैसे मुद्दे को बड़े गंभीर रूप से इसको उठाया गया। परिणामस्वरूप इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए मनिस्टरी द्वारा ठेका प्राप्त कंपनी से रजिस्टरेशन नं मोर्थ/इ/2019/04241 तिथि 22-08-2019 पत्र जारी किया गया। नैशनल हाईवे द्वारा इन मुद्दों की गंभीरता को समझते हुए इस पर जरूरी कदम उठाने के लिये दिशा-निर्देश दिए गए और इस पर लिखित रूप में कंपनी से जवाब मांगा। पर हास्यपद बात ये है कि ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा अपने जवाब में दलील दी गई है कि उनके द्वारा पी.ए.पी चौक का फ्लाई ओवर का निर्माण पूरा कर दिया गया है और रामांमंडी फ्लाई ओवर का काम खत्म होने के नजदीक है और उनके द्वारा हाईवे पर जमा पानी के लिए कसूरवार जनता को ठहराया गया है जिसमें कि कंपनी ने कुछ चित्रों के माध्यमों से ये समझाना चाहा कि हाईवे के आसपास बनी नालियां, कलवटों को लोगों द्वारा मलबा कूडा फैंक कर इसे बंद कर दिया गया है जिसके कारण बरसाती मौसम में हाईवे पर पानी जमा हो जाता है फिर भी टैंकरों, पंपों की मदद से इसकी निकासी की जाती है। इस जवाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नैशनल हाईवे विभाग और ठेका प्राप्त कंपनी फ्रैंडली मैच खेल रहे है जिसका मुख्य कारण ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा नामोशी भरा जवाब देना। ऐसे लगता है कि इस जवाब से ये प्रतीत हो रहा है कि ठेका प्राप्त कंपनी ये साबित करना चाह रही है कि हमने हाईवे के रखरखाव में कोई कमी नहीं छोड़ी जो भी कमी है वो लोगों द्वारा ही उत्पन्न की गई है अगर मान भी लिया जाए कि लोगों द्वारा हाईवे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो विभाग आंखें मूदकर इसे होता हुआ क्यों देख रहे है और इसकी रोकथाम के लिए जिस लोगों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है उन पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही और जोकि आम जनता से वसूला जा रहा टोल टैक्स किस हैसियत से वसूला जा रहा है क्योंकि ये प्रोजैक्ट बी.ओ.टी. मॉडल का है तो इसमें रखरखाव का सारा खर्चा ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा ही करना होता है। इस सारे वाक्य से प्रतीत हो रहा है कि ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा झूठी दलील नैशनल हाईवे के अधिकारियों को दी जा रही है। विभाग द्वारा इसे बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया गया है और ना ही हर शहर के जिलाधीश जो कि नोडल अफसर के रूप में नैशनल हाइवे का कार्य निरीक्षण करते है उनसे रिपोर्ट लेने के बजाये विभाग द्वारा बड़े स्तर पर ठेका प्राप्त कंपनी को लाभ पहुँचाया जा रहा है और लोगों की जान की कीमत को समझने की बजाए उनको मौत के मुंह में विभाग धकेल रहा है।

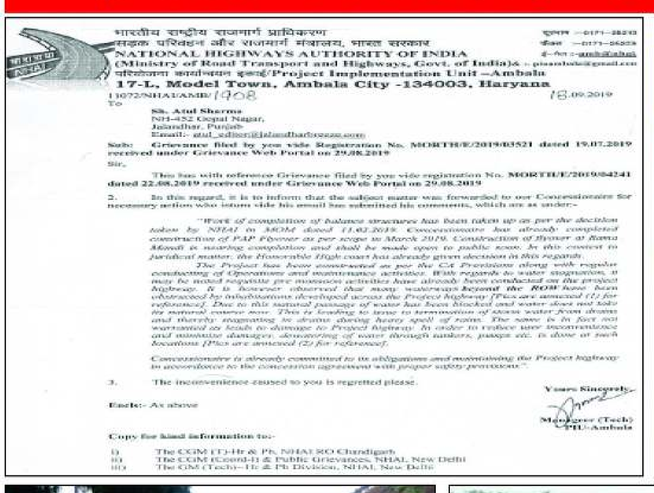

तुम ख्वाबों की दुनिया सजाते रहोगे
हम हकीकत की दुनिया बसाते रहेंगे

पिछले अंकों में छपी हुई तस्वीरें हकीकत बताती हुई

फ्रैंडली मैच खेल रहे नैशनल हाईवे विभाग और ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा नामोशी भरी दलीलों की तस्वीरें

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई/Project Implementation Unit –Ambala
17-L, Model Town, Ambala City -134003, Haryana

13072/NHAI/AMB/1908 — 18.09.2019

To
Sh. Atul Sharma
NH-452 Gopal Nagar,
Jalandhar, Punjab
Email:- atul_editor@jalandharbreeze.com

Sub: Grievance filed by you vide Registration No. MORTH/E/2019/03521 dated 19.07.2019 received under Grievance Web Portal on 29.08.2019

Sir,

This has with reference Grievance filed by you vide registration No. MORTH/E/2019/04241 dated 22.08.2019 received under Grievance Web Portal on 29.08.2019

2. In this regard, it is to inform that the subject matter was forwarded to our Concessionaire for necessary action who in turn vide his email has submitted his comments, which are as under:-

"Work of completion of balance structures has been taken up as per the decision taken by NHAI in MOM dated 11.02.2019. Concessionaire has already completed construction of PAP Flyover as per scope in March 2019. Construction of flyover at Rama Mandi is nearing completion and shall be made open to public soon. [illegible]

[illegible]"

3. The inconvenience caused to you is regretted please.

Encls:- As above

Yours Sincerely,
Manager (Tech)
PIU-Ambala

Copy for kind information to:-
i) The CGM (T)-Hr & Pb, NHAI RO Chandigarh
ii) The CGM (Coord-I) & Public Grievances, NHAI, New Delhi
iii) The GM (Tech)-Hr & Pb Division, NHAI, New Delhi

लाखों की कीमत वाली सरकारी जमीन पर बने सुविधा केन्द्र हो रहे हैं खंडर

भूतपूर्व सरकार द्वारा चालू की गई सुविधा केन्द्र की योजनाओं को सुचारू ढंग से लागू करवाने में असफल वर्तमान सरकार

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

अकाली-भाजपा सरकार द्वारा पूरे राज्य में आम जनता को अपने घर के पास ही सारी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने के उदेश्य से सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसमें 3 तरह के सेवा केंन्द्र काम करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाले सेवा केन्द्र टाइप-1 शहरी क्षेत्र वाले टाइप-2 और मुख्य सुविधा सैंटर (जो पहले काम कर रहे थे) उनको टाइप-1 की कैटेगरी में रखा गया है। आम जनता को अपने अपने घर के नजदीक बने हुए सुविधा केन्द्रों में भी सारी सेवाएं मिल रही है। सुविधा केंन्द्रों में उन सभी फार्मों को जो कंप्यूटर की मदद से भरा जाता है जैसे की राशन कार्ड, पैंनशन, बीमा, जन्म सार्टीफिकेट, डैथ सार्टीफिकेट, बैंक अकाऊंट, आधार कार्ड इत्यादि ऐसे ही और भी कई सारे जरूरी सरकारी कागज इस केंन्द्र से बनाए जा सकते है जो जरूरतमंद इंसान के काम आ सकते है। भारत सरकार ने हर जिले और शहर में कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर

दादा कलोनी में बंद पड़े सुविधा केन्द्र की तस्वीरें।

जन सेवा केन्द्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि आम जनता को सारी सुविधा और सेवा प्रदान कर सके, वैसे तो सरकार बड़े-बड़े दावे ढोकती थी पर ये सरकार की नाकामी की जीती जागती मिसाल है। सुविधा केन्द्र जो दादा कालोनी में स्थित है कई साल पहले इसका निर्माण किया पर अभी तक उसे हरी झंडी नहीं दी। अब लोगों ने उसका नाम सुविधा केन्द्र की बजाये दुविधा केन्द्र रख दिया है। कई सालों से पड़ा फर्नीचर भी गल गया अन्दर से बदबू का आलम बना हुआ है और ईमारत खंडर का रूप धारण कर चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गांव के बीच एक जन सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। वैसे तो देखा गया है कि कई जगहों पर सेवा प्रधान करने वाला सुविधा केन्द्रों में इंटरनेट सुविधा बंद होने से करीब 10 दिनों से सारा कार्य ठप्प पड़ा रहता है। लोग अपने काम करवाने के लिए धक्के खाने को मजबूर है। कई सुविधा केन्द्रों में देखा गया है कि कर्मचारी तो मौजूद थे लेकिन इंटरनेट न चलने से कामकाज ठप्प रहता है। वहीं लोग अपने काम करवाने के लिए रोजाना सेवा केन्द्रों के चक्कर लगा रहे होते है।

ट्विटर

यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर अनुभव कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा सुरक्षा व संरक्षा को और दुरुस्त करने की है।

-पीयूष गोयल, रेल मंत्री

उक्ति

"यदि आप किसी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आपको सभी काम करने का अधिकार होता है, लेकिन इसी के साथ यह कर्तव्य भी जुड़ा है कि आप जो करेंगे, सही करेंगे।

-मौलाना आजाद

दखल

अंधविश्वास से निजात आखिर कब

जादू टोना के नाम पर किसी के साथ ज्यादती की ओडिशा की घटना पहली नहीं है। देश में कई मौकों पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। मगर आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। यह घटना बताने के लिए काफी है कि समाज में बहुत सारे लोग वैज्ञानिक चेतना के अभाव में किस कदर किसी बीमारी के कारण पर विचार करने की स्थिति में नहीं पहुंच सके हैं।

ओडिशा के गंजम से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने जादूटोना करने के शक में छह बुजुर्गों के दांत तोड़ दिए और उन्हें मानव मलमूत्र खाने के लिए मजबूर किया। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। गोपुरपुर गांव के कुछ लोगों को शक था कि छह बुजुर्ग व्यक्ति जादूटोना कर रहे हैं, जिसके चलते उनके इलाके में कम से कम छह महिलाओं की मौत हो गई और सात अन्य बीमार हो गईं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मंगलवार को छह लोगों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला और उन्हें मानव मलमूत्र खाने के लिए मजबूर किया, बाद में उनके दांत उखाड़ दिए। इन छह ने मदद की गुहार भी लगाई लेकिन कोई भी उनके लिए आगे नहीं आया। जादू टोना के नाम पर किसी के साथ ज्यादती की यह पहली घटना नहीं है। देश में कई मौकों पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। मगर आज तक कोई समाधान नहीं हो सका।

यह घटना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच हमारे समाज में बहुत सारे लोग वैज्ञानिक चेतना के अभाव में किस कदर किसी बीमारी के कारण पर विचार करने की स्थिति में नहीं पहुंच सके हैं। यह एक जगजाहिर तथ्य है कि ऐसे अंधविश्वासों की वजह से देश भर में कितने लोगों और खासकर महिलाओं को त्रासद उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तांत्रिक या ओझा के बहकावे में आकार किसी महिला को डायन या काला जादू करने वाली बताने, उसे मैला पिलाने, निर्वस्त्र करके घुमाने और हत्या तक कर देने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। विडंबना है कि ऐसे अंधविश्वासों में पड़े लोगों को यह भी अहसास नहीं होता कि भ्रम में पड़ कर वे अपराध कर रहे हैं। कई बार धार्मिक परंपरा का नाम देकर ऐसी धारणाओं का बचाव किया जाता है। देश के कुछ राज्यों में जब अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने की कोशिशें की जा रही थीं, तो उसके विरोध के लिए धार्मिक पक्ष का ही हवाला दिया गया था।

साफ है कि अंधविश्वासों के बने रहने में कुछ लोग अपना हित समझते हैं और इसीलिए वैज्ञानिक सोच के बजाय भ्रम पर आधारित परंपराओं को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी आंदोलन और जागरूकता अभियानों की कमी नहीं रही है। इसके बावजूद आज भी देश में कहीं भी जादू-टोना या अंधविश्वास पर आधारित मान्यताओं की वजह से किसी की हत्या कर दी जाती है तो यह सोचने की जरूरत है कि व्यवस्थागत रूप से सामाजिक विकास के किन पहलुओं की अनदेखी की गई है। भारतीय संविधान की धारा 51-ए (एच) के तहत वैज्ञानिक दृष्टि के विकास और जरूरत को नागरिकों को बुनियादी कर्तव्य के रूप में रेखांकित किया गया है। पर आजादी से बाद से अब तक सरकारों की ओर से शायद ही कभी इस मकसद से कोई ठोस पहलकदमी की गई या वैज्ञानिक चेतना के विकास, उसके प्रचार-प्रसार को मुख्य कार्यक्रमों में शामिल किया गया। नतीजतन, परंपरागत तौर पर जिस रूप में अंधविश्वास समाज में चलता आया है, लोग उससे अलग कुछ सोचने की कोशिश नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि न केवल सामाजिक संगठनों, बल्कि खुद सरकार की ओर से भी शिक्षा-पद्धति में अंधविश्वासों के खिलाफ पाठ शामिल करने के साथ-साथ व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। अन्यथा अंधविश्वास की वजह से होने वाली घटनाएं हमारे तमाम विकास पर सवाल उठाती रहेंगी।

आज की तारीख में बाबाओं व तांत्रिकों का धंधा अंधविश्वास के कारण ही चल रहा है। सच कहा जाए तो अंधविश्वास फैलाने वाले काफी संगठित और मजबूत हैं, तभी तो उनका विरोध करने पर नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। संविधान में वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के संकल्प के बावजूद कार्यपालिका और विधायिका के स्तर पर अंधविश्वास से लड़ने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई देती। कुछ राज्यों में भले इस मामले में कानून बन गया हो, लेकिन ज्यादातर राज्य इसे लेकर उदासीन हैं। अक्सर जाने-अनजाने प्रशासन ही इसे बढ़ावा देता रहता है। अंधविश्वास विकास और तरक्की के रास्ते में बड़ी बाधा है। सरकार को चाहिए कि वह अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटे और लोगों को जागरूक करे। आज अंधविश्वास और अवैज्ञानिक सोच के खिलाफ सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। इसके लिए सरकार, सामाजिक-धार्मिक संगठनों को एकजुट होना होगा। शाब्दिक अर्थ में अंधविश्वास मनुष्य द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अज्ञानवंश किसी भी व्यक्ति-वस्तु पर आंख मूंदकर अडिग विश्वास करना कहा जा सकता है। जब उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि ऐसा करने से उसका व उसके अपनों का नुकसान हो रहा है और उसे मौत की राह पर ले जा रहा है। यह वही है जो उसकी सही-गलत की सोच ही खत्म कर देता है और मनुष्य अधोगति के रास्ते पर चल पड़ता है। यह बात और भी मन को दुखी करती है जब समाज व राष्ट्र को दिशा देने वाला शिक्षित वर्ग ही अंधविश्वास के जाल में फंसकर न जाने क्या-क्या कुकृत्य कर डालता है। खुद को मौत के चंगुल में झोंक देते हैं और वह भी महज अपनी या अपने करीबी की खुशी के लिए व धन की वृद्धि के लिए!

ऐसा ही एक वाकया दिल्ली के बुराड़ी में देखने को मिला था, जहां 11 लोगों ने अंधविश्वास में फंसकर खुदकुशी कर ली थी। ऐसे ही राजस्थान व महाराष्ट्र के अन्य उदाहरण भी हैं जहां परिवार के किसी सदस्य ने अंधविश्वास के कारण अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया या फिर पूरे परिवार ने सायनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। यह सोचनीय है कि इस तरह के कार्य करके ये लोग समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। कहा जाता है हमारा देश बाबाओं का देश है। लेकिन उनमें से अनगिनत ढोंगी बाबा भी खुद को स्थापित किए हुए हैं, जो भोले भाले लोगों को धन, विद्या, बीमारी के ठीक होने, मृत्यु दोष दूर करने, सौतन से छुटकारा पाने, संतान व बेटे की प्राप्ति आदि अनेक लालच देकर ना जाने क्या क्या कर्मकांड व टोने-टोटके करवाते हैं। ऐसे कार्यों से दूसरों का तो नुकसान होता ही है, साथ ही हम लोग खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं और इन ढोंगी बाबाओं का व्यापार चलता रहता है।

इनके यहां हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी बैठा मिल जाएगा। लालच के अंधकार में उन्हें अच्छा-बुरा कुछ नजर नहीं आता। होली-दिवाली, अमावस्या-पूर्णिमा की रात को पता नहीं कितने ही चौराहों पर कहीं न कहीं कुछ-कुछ रखा हुआ मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में कामाख्या देवी पर तो जीव बलि ही दी जाती है। इसके अलावा हर शहर में पेड़ के नीचे तंबू गाड़े इन जन्त्र-मंत्र वाले बाबाओं के खोखचे मिल जाएंगे। सामान्य तौर पर हमारे देश में बहुत तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं। ये न केवल अभी जागृत हुए हैं बल्कि इनकी जड़े प्राचीन काल से स्थापित हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, किसी काम की शुरुआत करते समय छींक आना, सूर्यग्रहण-चंद्रग्रहण में बाहर जाना, मंगलवार को बाल काटना, सांय के समय सफाई करना आदि अनेक कार्य हमारे समाज में अशुभ माने जाते हैं। लेकिन मूल कारणों को जाने बिना ही हम सभी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं।

रश्मि सिंह
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

विशेष संपादकीय

विकास की पटरी पर दौड़ती रेल

देश की कॉर्पोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस के लिए अब इंतजार खत्म हो गया है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ जं शन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे ने तेजस ए सप्रेस के किराए का भी ऐलान कर दिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन के विलंब होने पर मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे की सहायक कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि एक घंटे से अधिक का विलंब होने पर 100 रुपए की राशि अदा की जाएगी, जबकि दो घंटे से अधिक की देरी होने पर 250 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तेजस मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलेगी। छह अक्टूबर से ट्रेन सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर लखनऊ जंक्शन से छूटकर 7 बजकर 20 मिनट पर कानपुर और वहां से 7 बजकर 25 मिनट पर चलकर 11 बजकर 43 मिनट पर गाजियाबाद पहुंचेगी। यहां से 11 बजकर 45 मिनट पर छूटकर 12.25 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली से ट्रेन शाम 4 बजकर 30 मिनट पर रवाना होकर शाम 5 बजकर 10 मिनट पर गाजियाबाद, रात 9.30 मिनट पर कानपुर और रात 10 बजकर 45 मिनट पर लखनऊ आएगी। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन को पटरियों पर दौड़ते देखना वाकई सुखद है और रेलवे के कायाकल्प के लिए जरूरी भी। यह ट्रेन रेलवे की विस्तार नीति को बढ़ावा देगी और विभाग पर लगातार आ रहे बोझ से छुटकारा भी दिलाएगी। हालांकि, इस ट्रेन के बहाने रेलवे के निजीकरण को लेकर उठ रही शंकाओं का रेल मंत्री पीयूष गोयल समाधान कर चुके हैं, फिर भी यह ऐसा पहलू है, जिसकी तरफ एकबारगी नजर डालनी ही चाहिए। बहरहाल, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन की परिकल्पना सुरेश प्रभु की है। रेल मंत्री रहते प्रभु ने कहा था कि वो रेल के विकास के लिए निजी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, साथ ही राज्यों का भी सहयोग लेंगे। अगर मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में रेलवे के विकास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि विकास पटरी पर काफी आगे निकल गया है। रेलवे ने एक नई सेवा का ऐलान किया है। इस सेवा के जरिए टिकट बुक करवाते समय भले ही उन्हें कंफर्म टिकट न मिले, मगर उन्हें यह जरूर पता चल जाएगा कि उनके वेट लिस्ट टिकटों के कन्फर्म होने संभावना कितनी है। लोगों को ट्रेनों में खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत रहती है। अभी राजधानी और शताब्दी में खाने की अधिक मात्रा दी जाती है। भारतीय रेलवे अब ऐसी ट्रेनों में खाने की मात्रा कम करेगी, ताकि इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। भारतीय रेलवे का नेटवर्क विशालकाय है। इस वजहे से इसमें बदलाव की संभावनाएं और गति काफी सुस्त रहती है। हर जगह एक साथ बदलाव पहुंच पाना संभव भी नहीं है, मगर यदि समय पर सही प्रयास किया जाए, तो परिवर्तन लाया जा सकता है।

ठोस कचरे की बढ़ती चुनौती

कचरा प्रबंधन विश्व की मु य समस्याओं की सूची में ऊपर आता जा रहा है। कचरे की समस्या अब शहरों की बदसूरती तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह जल और वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन चुकी है। कचरे का संबंध स्वास्थ्य से भी है। कुछ दशकों में प्लास्टिक कचरे ने तो पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को इसे अपने सोच-विचार का विषय बनाना पड़ा है। भारत में भी स्वच्छता को लेकर पांच साल का एक अभियान पूरा हो चुका है। जाहिर है, इस अभियान के दौरान ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर जो मुश्किलें सामने आईं, उनसे भी सबक या अनुभव मिले हैं। कुछ दिनों तक हिसाब लगाया जाएगा कि कचरे के निस्तारण का काम कितना बढ़ पाया, और जो काम नहीं हो पाया, वह क्यों नहीं हो पाया। अड़चन कहां आई? आगे से उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए? बेशक स्वच्छता अभियान शुरू होते समय लगा नहीं था कि लक्ष्य इतना बड़ा और इतना पेचीदा होगा। फिर भी योजनाकारों के पास पक्के शौचालय आदि की जरूरत का मोटा अंदाजा जरूर था। लिहाजा, उस काम के लिए अलग से कर के जरिए संसाधनों का इंतजाम भी कर लिया गया। लेकिन स्वच्छता अभियान में ठोस कचरा प्रबंधन के मद वाला काम उस पैमाने पर होता नहीं दिखा। हो सकता है कि इसका एक कारण यह रहा हो कि पक्के तौर पर हमें यह नहीं पता था कि उद्योगों और घर-घर से निकले कचरे की वास्तविक मात्रा कितनी है? न ही यह हिसाब लगा था कि इस कूड़े को अगर जमा कर भी लिया जाएगा तो नई व्यवस्था में कचरे के उस भारी-भरकम ढेर को निस्तारित कैसे करेंगे? कचरे के इस निपटान के काम का एक तकनीकी नाम हमारे पास जरूर था, जिसे हिंदी में ठोस कचरा प्रबंधन कहते हैं। लेकिन अपने देश में यह प्रबंधन कितना भारी काम है, इसका शोधपरक ज्ञान या कोई अनुमान उपलब्ध नहीं था। बहुत संभव है कि सफाई की मुहिम के पांच साल में सबसे ज्यादा दिक्कत ठोस कचरा प्रबंधन में ही आई हो। नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में घर-घर से कचरा इकट्ठा करने में भारी खर्च करके कचरा जमा करने का कुछ काम होता तो दिखा, पर उसे ठिकाने लगाने के लिए जगह की कमी पड़ती चली गई। पिछले पांच साल का अनुभव बता रहा है कि शहरी कचरे के पहाड़ों को और ऊंचा करना अब मुमकिन नहीं है। कचरे को गाड़ने या दबाने के लिए भी जमीन कम पड़ने लगी है। भूगर्भीय प्रदूषण की समस्या अलग है। अगर कूड़े का निपटान आज इतनी बड़ी समस्या बन गई है तो उसका समाधान खोजने से पहले एक नजर इतिहास पर भी डाल लेनी चाहिए। आज से कोई ढाई हजार साल पहले तक यूनान और रोम जैसे देशों के विकसित नगरों में भी कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं थी। लोग घर के बाहर ही कचरा फेंका करते थे। प्रति व्यक्ति जमीन बहुत थी। आबादी थोड़ी होने से कचरा भी कम निकलता था। उस कूड़े का प्रकार भी अलग था। वह जल्दी ही आक्सीकृत हो जाता था। उसके बाद आबादी बढ़ती गई। कूड़े की

विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। यह चिंता इसलिए है कि प्लास्टिक सदियों तक गलता-मिटता नहीं है। प्लास्टिक की चिंता इस कारण से है कि यह प्लास्टिक कचरा आखिर में समुद्र में जाकर जमा हो रहा है और इस कचरे ने महासागरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। समस्या का विस्तार गली-कूचे से लेकर महासागरों तक हो चुका है।

मात्रा बढ़ती गई। कूड़े को राज्य सीमाओं के बाहर फेंका जाने लगा। फिर नगर बड़े होते गए तो सीमाएं दूर होने लगीं और कूड़े की ढुलाई का काम मुश्किल होता गया। तब नदियों में कचरा बहाने जैसे तरीके अपनाए जाने लगे। कचरे को बहाए जाने की भी एक सीमा थी। यह प्रवृत्ति पूरे विश्व में उनीसवीं सदी तक आते-आते बदल गई। उसके बाद कूड़े को जलाना शुरू हो गया। लेकिन बढ़ती आबादी और विकास की होड़ में इस समस्या का आकार बढ़ता ही चला गया।

साल भर पहले तक देश में सालाना सवा छह करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होने का अनुमान था। इस कचरे में ह्श्वलास्टिक, ई-कचरा और दूसरा खतरनाक कचरा भी शामिल है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जहां यह कचरा पैदा होता या निकलता है, वहां से इसे उठाने का इंतजाम भी नगर पालिकाएं या नगर निगम नहीं कर पा रहे थे। दावा यह किया जाता है कि पूरे देश के स्थानीय निकाय सिर्फ सवा चार करोड़ टन कचरा जमा कर पाते हैं। यानी दो करोड़ टन कचरा अपने उद्गम स्थल पर ही इधर से उधर होता रहता है। या फिर बारिश में नालियों के जरिए नदियों में जा रहा है। जहां तक ठोस कचरे के निस्तारण का सवाल है तो सिर्फ एक करोड़ बीस लाख टन कूड़े का शोधन करके उसका निस्तारण किए जाने का दावा किया जाता है, यानी जम किए गए सवा चार करोड़ टन कचरे में से सिर्फ सवा करोड़ टन कूड़े का निस्तारण होता है। इस तरह हर साल कुल कचरे का सिर्फ बीस फीसद हिस्सा हम उपचारित कर पाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी स्तर पर ही तीन करोड़ टन कूड़े को किसी न किसी जगह या फिर लैंडफिल साइट पर सड़ने-गलने के लिए डालने की मजबूरी है। संयुक्त राष्ट्र की चिंता प्लास्टिक कचरे को लेकर है। यह चिंता इसलिए भी है कि प्लास्टिक सदियों तक गलता और मिटता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक की चिंता इस कारण से है कि यह प्लास्टिक कचरा आखिर में समुद्र में जाकर जमा हो रहा है और इसने महासागरों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। समस्या का विस्तार गली- कूचे से लेकर महासागरों तक हो चुका है। अगला सवाल समाधान का है। सुझाव नया नहीं, बल्कि बार-बार दोहराया जाता रहा है कि गीले कूड़े से खाद और ज्यादातर सूखे कचरे का पुनर्चक्रण ही तरीका है। रसोईघर से निकलने वाले गीले कूड़े से बिजली बनाने की बातें भी बहुत पहले से हो रही हैं। प्रायोगिक स्तर के तमाम मॉडल भी पेश हुए हैं। कचरे के पुनर्चक्रण के मॉडल भी बहुतायत में दिखाए गए हैं, लेकिन औद्योगिक स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर यह काम होता नहीं दिखा। आखिर क्यों? इसका जवाब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कचरे का पुनर्चक्रण मुनाफे का सौदा नहीं है। यह आर्थिक रूप से फायदेमंद काम होता तो प्लास्टिक कचरे को फौरन ही गायब होने से कोई ताकत नहीं रोक पाती। कचरा बीनने और उसे पुनर्चक्रण के लिए तैयार करने में जितना खर्च आता है, उससे सस्ता तो नया कच्चा प्लास्टिक बाजार में उपलब्ध है। यानी कूड़े के उपचारण का काम उसे ठिकाने लगाने के लिए तो हो सकता है, पर उसे लाभकारी काम नहीं बनाया जा सकता। सवाल है कि आखिर पूरे कचरे को उपचारित करने में दिक्कत क्या है? सरकारें मानें या न मानें, दिक्कत सिर्फ एक है कि ठोस कचरे का निस्तारण बहुत खर्चीला है। अर्थव्यवस्थाओं में पुनर्चक्रण जैसे काम को उत्पादक प्रकार का नहीं माना जाता।

इसलिए इतने भारी-भरकम धन का प्रबंध कोई भी सरकार क्यों करना चाहेगी? इतना सरकारी खर्च अगर गैर-उत्पादक काम पर होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आमतौर पर सरकारों को महंगाई से डर लगता है। अगर वाकई मसला खर्चे का है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि देश जल्द से जल्द साफ-सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन पर खर्च करने लायक माली हैसियत हासिल करे या विज्ञान प्रौद्योगिकी वह तरीका ईजाद करे जिससे कचरे के पुनर्चक्रण का काम आर्थिक रूप से फायदे का बन जाए।

देश में एनआरसी की जरूरत है?

भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, किसी भी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थी को देश से जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं, घुसपैठियों को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। एनआरसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। नेताजी इंडोर स्टेडियम में एनआरसी पर आयोजित सेमिनार में शाह ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर एनआरसी को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एनआरसी को लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पास कराकर सभी हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। शाह ने कहा कि मुयमंत्री ममता बनर्जी ने ही चार अगस्त-2005 को संसद में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। अब वे अपने कथन से मुकर रही हैं। घुसपैठियों को देश से बाहर करने को लेकर गृहमंत्री शाह के बयान से सियासत गरमा गई है। बता दें कि असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर का आखिरी मसौदा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में तैयार किया गया था, जिसमें इसका खुलासा होने पर पार्टियों ने इसे राजनीतिक पैंतरा बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में तो यह राजनीति की धुरी बनता जा रहा

गृहमंत्री अमित शाह ने एनआरसी पर रुख स्पष्ट करते हुए कहा, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थी को देश से जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं, घुसपैठियों को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। इस पर बवाल मचा है, पर घुसपैठियों की पहचान से किसी को दिकत नहीं है।

है। हालांकि, गृहमंत्री ने विवाद पैदा होने के बाद स्पष्ट किया था कि अभी भी लोगों के पास एनसीआर में शामिल होने का मौका है लेकिन राजनीतिक लाभ लेने वाले ऐसे स्पष्टीकरण का कोई मूल्य नहीं रह जाता। फिर धड़ाधड़ की जा रही बयानबाजी से समाज दो वर्गों में बंट चुका है। एक विरोध करने वाले, दूसरे समर्थन करने वाले साथ ही देशभक्ति और देशद्रोहियों के फरमान जारी होने लगे हैं। यह पूरा मामला दरअसल आगामी चुनावों को लेकर जारी है। असम और बंगाल की सीटों की संख्या बहुत ही अहम है। देश की राजनीति की खासियत बन गई है कि समाज को बांटना। अच्छी बात यह होती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रैलियों की भाषणबाजी में न लाया जाता, अदालत का काम अदालत करती व राजनेता अपना काम करते और सरकार जो कर रही है, उसे करने दिया जाए। राजनीतिक शिगूफेबाजी समाज में अमन-शांति को प्रभावित करती है एवं इससे राजनीतिक हिंसा बढ़ती है। केरल में पहले ही राजनीतिक हिंसा के भयानक परिणाम सामने आ चुके हैं, जिससे सीख लेनी चाहिए थी। एक तरफ प्रधानमंत्री भीड़ द्वारा हिंसा की निंदा करते हुए सती इस्तेमाल करने का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनआरसी के नाम पर राजनेता दो वर्गों में सीधे टकराव का माहौल बना रहे हैं। एनआरसी देश की जरूरत और कानूनी प्रक्रिया में से या है, यह बहस का प्रश्न है, लेकिन इसकी आड़ में देश को विभाजित करना सरासर गलत है। जहां तक सवाल देश में घुसपैठियों की पहचान का है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863,

All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

बड़े काम के हैं ये 20 सरकारी एप

हर भारतीय को करने चाहिए डाउनलोड

भारत सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया के तहत समय-समय पर नागरिकों की सुविधा के लिए सरकारी एप लांच किए गए। इनमें एम-पासपोर्ट सेवा एप लांच भी शामिल है, जिससे अब कहीं से भी लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सी-विजिल एप लांच किया गया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर चुनाव के दौरान होने वाली अवैध गतिविधियों की फोटो और वीडियो और हेट स्पीच जानकारी दे सकता है। यहां ऐसे 20 सरकारी एप की लिस्ट दी गई है, जो कि आम नागरिकों के लिए काफी सुविधाजनक हो सकते हैं।

इंडियन पुलिस एप

इस एप के उपयोग से लोग अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन की लोकेशन पता कर सकते हैं। एप पर रूट की जानकारी, दूरी और कैसे नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंचा जाए। इसकी पूरी जानकारी दी गई है। एप की मदद से जिला पुलिस कंट्रोल रूम और एसपी ऑफिस के नंबर हासिल किए जा सकते हैं। इसकी मदद से मात्र एक फोन कॉल से मदद हासिल की जा सकती है।

ई-पाठशाला

इस एप को मानव संसाधन मंत्रालय और एनसीईआरटी के साझा सहयोग से विकसित किया गया है। ई-बुक को मोबाइल फोन, टेबलेट, डेस्कटॉप पर छात्र और अध्यापक आसानी से पहुंच सकते हैं। एक आदमी कई किताबों को डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में संरक्षित कर सकता है। एप में जरूरी दस्तावेजों पर पिंच, सेलेक्ट, हाइलाइट और यहां तक कि टेस्ट को स्पीच में बदलकर सुन सकते हैं।

एम-परिवहन एप

इस एप के जरिए यूजर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी ले सकते हैं। इसके साथ ही दो पहिया और चार पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जा सकता है। गाड़ी चालक अपनी कार के रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपनी सेकंड हैंड कार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो लोग अपनी पुरानी कार को बेचना चाहते हैं, वो यहां अपनी उम्र और ब्योरो की जांच करा सकते हैं।

स्टार्टअप इंडिया

इस एप को नए उद्यमियों को स्टार्टअप इको सिस्टम के बारे में सूचनाएं मुहैया कराने और समझाने को लेकर डिजाइन किया गया। एप कि जरिए यूजर अपनी सरकार की स्टार्टअप को लेकर शुरू की गई योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

डिजी सेवक एप

भारत की बेहतरी के लिए वालिंटियर के रूप में काम करने वालों को इस एप से काफी मदद मिल सकती है। वालिंटियर की क्षमता, स्किल और जिज्ञासा के आधार पर कई तरह के कार्य दिए जाते हैं। इस एप पर सरकार के कई मंत्रालयों के विभाग में जरूरतों को दर्शाता गया है। लोग एप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ टास्क का मूल्यांकन कर सकते हैं।

जीएसटी रेट फाइंडर

अगर आप जीएसटी रेट को लेकर संशय में हैं, तो यह एप आपकी मदद कर सकता है। यहां वस्तु एवं सेवा कर के रेट दिए रहते हैं। एप को डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

उमंग

इसे इलेक्ट्रानिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन ने बनाया है। यह एप सरकार के सभी मंत्रालयों और उनकी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराता है, जिससे लोगों को आसानी से सूचना मिल सके। यह डिजिटल इंडिया, आधार, डिजी-लॉकर की तरह कार्य करता है।

इंक्रेडिबल इंडिया

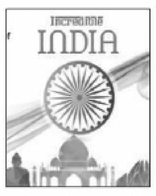

इस एप के जरिए पर्यटन से जुड़ी सूचनाएं इकट्ठा की जा सकती हैं। इस पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन की जानकारी उपलब्ध होती है। एप पर ट्रेवेल एजेंट, रीजनल लेवेल गाइड और होटल और शहरों के सेंटर की जानकारी उपलब्ध होती है।

एम-पासपोर्ट

जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। इस एप के माध्यम से स्मार्टफोन उपभोक्ता एक क्लिक पर पासपोर्ट से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन, पासपोर्ट की लोकेशन, पासपोर्ट सेवा केंद्र और अन्य सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

एम-आधार एप

आधार एप केवल एड्राइड उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को स्मार्टफोन पर आधार आईडी मुहैया कराना है। इस एप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार केवाईसी इन्फार्मेशन देने के बाद आप इसे बतौर आईडी प्रयोग कर सकते हैं। क्यूआर कोड के जरिए भी लोग अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। यूआईडीओआई ने दावा किया है कि एप उपभोक्ता को अपना बॉयोमैट्रिक डाटा ब्लॉक करने की इजाजत देता है।

पोस्ट इंफो

इसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। एप पार्सल की ट्रैकिंग, पोस्ट आफिस, पोस्टेज कैलकुलेटर, इंश्योरेंस प्रीमियम और ब्याज की गणना की सुविधा उपलब्ध कराता है। पोस्टल विभाग कई तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराता है।

माई गवर्मेंट

माई गवर्मेंट एप लोगों को गवर्नेंस से जुड़ने का प्लेटफार्म मुहैया कराता है, जहां लोग अपने आइडिया, कमेंट और सुझाव मंत्रालय और उनके विभाग तक पहुंचा सकते हैं। इन विचारों का उपयोग योजना बनाने में किया जाता है।

माई स्पीड

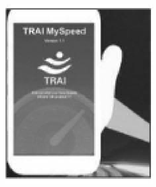

यह एप्लीकेशन आपको डाटा स्पीड एक्सपीरियंस और उनके परिणाम को ट्राई को भेजने का काम करता है। एप्लीकेशन लोकेशन की जानकारी देता है। एप कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देता है। सभी परिणाम अपने आप आते हैं। यह एप आपकी डाटा स्पीड की जानकारी ट्राई को देता है। डाटा की सही स्पीड न मिलने पर उपभोक्ता इस एप के जरिए ट्राई को सूचना दे सकता है।

एम कवच

एप केवल एंड्राइड डिवाइस पर उपलब्ध रहता है। इस एप का उद्देश्य मोबाइल फोन पर मिलने वाली धमकियों की शिकायत की जा सकती है। साथ ही तुरंत स्पैम एमएमएस को ब्लॉक किया जा सकता है। इसके साथ ही एप मालवेयर को लेकर आगाह करता है।

स्वच्छ भारत अभियान

जैसा की नाम से मालूम होता है। एप भारत के शहरों और गांवों की स्वच्छता से संबंधित है। एप के जरिए लोग अपने इलाके की गंदगी के फोटो खींचकर संबंधित नगर निगम तक पहुंचा सकते हैं। सभी शहरी क्षेत्रों के नगर निगम इस एप पर उपलब्ध हैं, जहां से उचित जगह के फोटो की पहचान करके तत्काल वहां पहुंचा दिया जाता है। इसके लिए जीयो लोकेशन की मदद ली जाती है। इस पर लोग अपने फीडबैक दे सकते हैं।

भीम एप

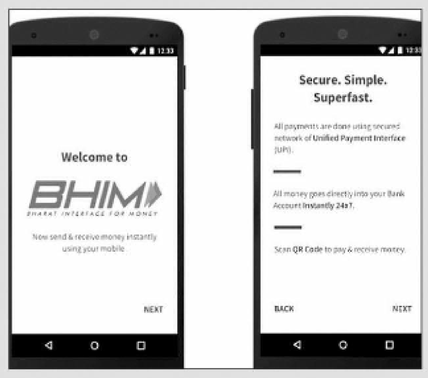

इसके जरिए पैसों का आसानी से ट्रांसफर किया जाता है। भीम एप यूपीआई (यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस) पर आधारित है। इसके जरिए यूपीआई पेमेंट की मदद से पता, फोन नंबर और क्यूआर कोड से पैसों का लेनदेन किया जा सकता है। देश के सभी बैंक यूपीआई से लिंक होते है।

आईआरसीटीसी

यह सरकार का सबसे लोकप्रिय एप है, इससे ट्रेन की बुकिंग की जा सकती है। इसके जरिए जल्दी और आसानी से टिकट कराया जा सकता है।

आयकर सेतू

इस पर आयकर विभाग की कई सेवाएं जुड़ी रहती हैं। इसमें कई उपयोगी फीचर है। इसकी मदद से ऑनलाइन टैक्स की अदायगी की जा सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन पैन का आवेदन किया जा सकता है। वहीं, टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। इस पर एक चैटबोट मौजूद होता है, जो कि टैक्सपेयर को सूचनाएं मुहैया कराता है।

किसान सुविधा एप

इस एप का विकास किसानों की सुविधा के लिए किया गया। यहां से किसान मौसम, मार्केट प्राइस और प्लैनेट प्रोटेक्शन की जानकारी हासिल कर सकता है।

सी-विजिल

चुनाव आयोग की ओर से इस सी-विजिल एप को लांच किया गया है। इसके जरिए व्यक्तिगत तौर पर वीडियो और फोटो और हेट स्पीच की जानकारी दी जा सकती है।

व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं अभद्र संदेश या धमकी, तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

अगर आप व्हाट्सएप (Whatsapp) पर मिल रहे अभद्र और आपत्तिजनक संदेशों से परेशान हैं तो अब चिंता की जरूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत दूरसंचार विभाग के पास दर्ज करा सकते हैं और विभाग इसे कार्रवाई के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और पुलिस के पास भेजेगा।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि व्हाट्सएप पर प्राप्त आपत्तिजनक संदेशों के खिलाफ अब लोग दूरसंचार विभाग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पीड़ित को मोबाइल नंबर के साथ संदेश का स्क्रीनशॉट लेकर ccaddn-dot@nic.in ई-मेल करना होगा। दूरसंचार विभाग के संचार नियंत्रक (कंट्रोलर कम्युनिकेशंस) आशीष जोशी ने ट्वीट में कहा है कि यदि किसी को भद्दे, आपत्तिजनक, जान से मारने की धमकी या अश्लील व्हाट्सएप संदेश मिलते हैं तो वह मोबाइल नंबर के साथ संदेश के स्क्रीनशॉट को ccaddn-dot@nic.in पर भेजे दें। उन्होंने कहा कि जरूरी कार्रवाई के लिए इसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। उन्होंने बताया कि कई लोग और लोकप्रिय हस्तियां अभद्र और धमकी भरे संदेश मिलने की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। डीओटी ने 19 फरवरी को एक आदेश में कहा था कि लाइसेंस की शर्तें नेटवर्क पर आपत्तिजनक, अश्लील, अनाधिकृत या किसी अन्य रूप में गलत संदेश भेजने पर पाबंदी लगाती हैं। आदेश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को गलत संदेश भेजने वाले ग्राहकों पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, चूंकि यह ग्राहक आवेदन फॉर्म में की ग्राहक घोषणा का उल्लंघन भी है।

क्या आप जीमेल में दी गई इन खूबियों के बारे में जानते हैं?

जीमेल दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली मेल सर्विस है, जिसमें रोज करोड़ों मेल भेजे और रिसीव किए जाते हैं। जीमेल का लुक पिछले कुछ सालों में काफी बदला है, इसे यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए गूगल समय-समय पर छोटे-छोटे बदलाव करता रहता है। जीमेल में इसके चलते ऐसे कई नए फीचर जोड़े गए हैं, जो रेगुलर यूजर को पता नहीं चलते। हम आपको 10 ऐसी ही जीमेल ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप इस पॉपुलर मेल सर्विस को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं।

ईमेल से अपनी फाइल डायरेक्ट एक्सेस करें

आजकल ड्रॉपबॉक्स ऑनलाइन डेटा सेव करने के लिए काफी प्रयोग किया जा रहा है, अगर आप भी ड्रॉपबॉक्स का प्रयोग करते हैं और आप ड्रॉप बॉक्स को क्विक ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए ड्रॉपबॉक्स की फाइल को जीमेल में अटैच करके उसे ड्राफ्ट में सेव कर दें। जब भी आपको जरूरत हो ड्रॉपबॉक्स की फाइल तुरंत ओपन कर सकते हैं।

अपनी होम आईपी एड्रेस से ट्रैक करें

ऐसी कई सर्विस हैं, जिनको प्रयोग करने के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, जैसे रिमोट कंट्रोल एक्सेस, मीडिया स्ट्रीमिंग। मगर आईपी एड्रेस समय समय पर बदलते रहते हैं। DynDNS की मदद से आप अपने सभी आईपी एड्रोस को ट्रैक कर सकते हैं। हालाकि इसके लिए आपको थोड़ा चार्ज भी देना पड़ सकता है।

जीमेल टेक्ट फार्मेट में बदलाव करें

अगर आप हमेशा जीमेल में कुछ भी कॉपी पेस्ट करने से पहले उसे नोटपैड में पेस्ट करके फिर जीमेल में डालते हैं। तो इसके लिए जीमेल में दिए गए Remove Formatting बटन पर क्लिक कर दें। अब आप जो भी जीमेल में पेस्ट करेंगे वो बिल्कुल उसी फार्मेट में पेस्ट होगा, जैसा कॉपी करेंगे।

कॉन्टेक्ट लिस्ट रीस्टोर करें

शायद आपको न पता हो मगर जीमेल आपकी फोन में सेव कॉटेक्ट को सेव कर लेता है यानी अगर धोखे से आपके फोन में सेव सारे कांटेक्ट डिलीट हो जाते हैं जो जीमेल की मदद से आप उसे दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं।

मैसेज में डायरेक्ट इमेल कॉपी पेस्ट करें

जीमेल मैसेज में कुछ टेक्ट के अलावा आप सीधे इमेज कॉपी करके उसे पेस्ट कर सकते हैं।

अपना क्रेडिट स्कोर केवल एक मिनट में निःशुल्क जांचे

यहां क्लिक करें और निःशुल्क अपना क्रेडिट स्कोर जांचे, जल्दी करें!

गूगल डॉक्स

अगर आपके जीमेल में कम स्पेस बचा है तो अपनी सारी मेल को गूगल डॉक्स में सेव कर सकते हैं और अलग-अलग साइज के हिसाब से उसे सेट भी कर सकते हैं।

आईओएस में कैसे सेट करें जीमेल?

अगर आप आईओएस में जीमेल ओपन करते हैं तो आपके आईओएस फोन में सेव सारी कांटेक्ट जीमेल में सिंक हो जाएगा। अब आप जहां भी अपनी जीमेल ओपन करेंगे, आपको आईओएस कांटेक्ट मिल जाएंगे।

कूड़े के टेर ने स्वच्छ भारत अभियान की पूरी तरह से हवा निकाली

■ जालंधर/नीरज

देश में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की झलक आपको रामामंडी पुल के आसपास साफ दिखाई देगी। अगर आप होशियारपुर से जालंधर की और रामामंडी की और से आ रहे है तो पुल चढने से पहले ही आपका पुल के पास लगा कूड़े ढेर आपका स्वागात करेगा और उससे पहले भी आपको डिवाईडर के किनारे कूड़े के ढेर लगा हुआ वहा पर आसपास के दुकानदारों ने पौधारोपण किया गया था ताकि माहौल को स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन रामामंडी में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर स्वच्छ भारत अभियान की पूरी तरह से हवा निकल रहे है।

इसका मुख्य कारण है कि लोगों के पास कूड़ा फैकने के लिए कोई जगह नहीं है और रात के समय पुल पर या उसे आसपास कूड़ा फैक जाते है।

इसका कहीं ना कहीं इलाके के पार्षद भी प्रशासन के साथ साथ जिम्मेवार है जो आपना फर्ज भूले बैठे है।

इलाके के पार्षद कूड़ा फैकने के लिए अभी तक रामामंडी में स्थाईरूप से कोई जगह लोगों को उपलब्ध नहीं करवा सके है।

शेख हसीना से मिले मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, हसीना ने प्रियंका गांधी को गले लगाया

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अगुआई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी में हसीना से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शेख हसीना से मुलाकात की, हसीना ने उन्हें गले भी लगाया। बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की सदस्य नहीं थीं। हसीना से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, शेख हसीना जी से मुलाकात हुई जिनसे दोबारा मिलने की काफी समय से इच्छा थी। गहरे निजी नुकसान एवं बुरे वक्त से उबरने की उनकी ताकत और बहादुरी एवं दृढ़ता से अपने विचारों के लिए उनका संघर्ष हमेशा से मेरे लिए एक प्रेरणा है। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, अवामी लीग के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और नेहरू गांधी परिवार और शेख हसीना जी के परिवार के बीच निजी संबंध हैं। मित्रता और सम्मान का रिश्ता इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर्रहमान के बीच थे। आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में बांग्लादेश की तरक्की के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने प्रधनमंत्री शेख हसीना को बधाई दी। बांग्लादेश की प्रगति में भारत के योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। आनंद शर्मा ने बताया कि शेख हसीना ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बंग्लादेश आने का न्योता भी दिया।

उन्होंने कहा, जल्द ही बांग्लादेश अपनी आजादी की पचासवीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने जा रहा है। इसके लिए शेख हसीना ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को न्यौता दिया है। सोनिया गांधी ने न्यौता स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश की आजादी में इंदिरा गांधी का योगदान था। प्रियंका गांधी को गले लगाने के लेकर आनंद शर्मा ने कहा, शेख हसीना ने प्रियंका गांधी को गले लगाया ये बताता है कि बेहद आत्मीयता और प्रेम का संबंध है। उनके मन में मातृत्व की भावना थी प्रियंका के लिए जो उमड़ी और उन्होंने गले लगाया।

जोशीले भाषण से इंटरनेट स्टार बनीं कांस्टेबल खुशबू चौहान, सीआरपीएफ ने तारीफ के साथ संयम बरतने की सलाह दी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल खुशबू चौहान का भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उनके धारदार भाषण की तारीफ हो रही है। लेकिन उनके भाषण के कुछ हिस्सों पर कड़ी आपत्ति भी जताई जा रही है। इस बीच सीआरपीएफ ने बयान जारी कर खुशबू की तारीफ तो की है लेकिन बोलने में संयम बरतने की हिदायत भी दी है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कहा, हमारी एक महिला कांस्टेबल का भाषण वायरल हो रहा है. इसकी कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं और कुछ इसकी निंदा कर रहे हैं। यह भाषण 27 सितंबर 2019 को एनएचआरसी सीएपीएफ

वाद-विवाद प्रतियोगिता 2019 में दिया गया था। इसमें विषय था आतंकवाद और देश में मिलिटेंसी से मानवाधिकारों का पालन करते हुए कैसे प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

सीआरपीएफ ने कहा, सीएपीएफ ने हर संगठन के दो वक्ताओं को बोलने का मौका दिया था, जिसमें से एक को पक्ष में और एक को विपक्ष में बोलना था। उन्होंने सीआरपीएफ का प्रतिनिधित्व किया और विपक्ष में बात की। वीडियो सीआरपीएफ ने आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया है।

सीआरपीएफ ने कहा, भाषण एक वाद-विवाद प्रतियोगिता में दिया गया था और इसमें कुछ भी बुरा मानने लायक नहीं है। हम सी.आर.पी.एफ में मानवाधिकारों का बिना शर्त सम्मान करते हैं। उन्हें इस प्रस्ताव के खिलाफ बोलने के लिए कहा गया और उन्होंने भाषण दिया लेकिन कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए थी।

उन्हें उचित सलाह दी गई है। हम सीआरपीएफ के लिए सम्मान और चिंता की सराहना करते हैं।

जिस पंक्ति पर जताई जा रही है आपत्ति

खुशबू चौहान कहती हैं जब सीमा पर जवान शहीद होता है तो कोई मानवाधिकार की दुहाई नहीं देता लेकिन जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं तो सब उनके साथ खड़े हो जाते हैं।

भाषण में वह आगे कहती हैं, जो कहता है कि हर घर से अफजल निकलेगा तो मेरी बात सुन लो- जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा।

जवाहर लाल नेहरू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर खुशबू कहती हैं,उठो देश के वीर जवानों..तुम सिंह सी दहाड़ दो, और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो।

मानसा में 900 किलो मिलावटी देसी घी जब्त

देसी घी में मिलाया जाता था हरियाणा का बना हुआ कुकिंग मीडियम

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

मिलावटखोरों पर एक बार फिर से कड़ी कार्यवाही करते हुए फूड सेफ्टी की टीम ने मानसा के एक फूड बिजनेस ऑप्रेटर से 900 किलो मिलावटी देसी घी जब्त किया है, यह जानकारी खाद्य और ड्रग प्रबंधन पंजाब के कमिश्नर श्री काहन सिंह पन्नू ने दी।

उक्त उत्पादक घी में कुकिंग मीडियम मिलाकर विभिन्न ब्रांडों के देसी घी तैयार करने में संलिप्त था। टीम को 222 लीटर मधु सागर देसी घी के 12 बक्से, 550 लीटर केशव घी के 35 बक्से और 125 लीटर डेयरी किंग कुकिंग मीडियम के 12 बक्से मिले। श्री पन्नू ने बताया कि मिलावटखोरी करने के लिए हरियाणा में तैयार हुए कुकिंग मीडियम का प्रयोग किया जाता था और इसकी जांच की जा रही है कि कुकिंग मीडियम पड़ोसी राज्य से क्यों खरीदा जा रहा था।

इस दौरान फूड सेफ्टी टीम मानसा ने देसी घी और कुकिंक मीडियम के सैंपल लिए और जांच के लिए स्टेट लैब भेज दिए और उक्त फूड बिजनेस ऑप्रेटर की इमारत सील कर दी।

डेरा बाबा नानक हलके के लिए हरसिमरत अपने ससुराल और पति के राज में किया एक भी काम गिनवाए : सुखजिंदर सिंह रंधावा

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

सीनियर कांग्रेसी नेता और कैबिनेट मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पर धार्मिक समागमों का सियासीकरण और 550वें प्रकाश पर्व समागमों पर राजसी रोटियाँ सेकने का दोष लगाते हुए कहा कि वह धर्म की आड़ में राजनीति करने की बादल परिवार की पुरानी आदत को आगे ले जा रही है। स. रंधावा ने डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारे के काम को देखने के बहाने राजनीति करने आई हरसिमरत बादल के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उसने कहा थी कि राज्य सरकार की तरफ से कोई विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है। स. रंधावा ने हरसिमरत बादल को बदले में जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले ही डेरा बाबा नानक हलके के लिए 117 करोड़ रुपए के विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री यह बताए कि जब राज्य में उसका ससुर मुख्यमंत्री था, पति उपमुख्य मंत्री था और भाई कैबिनेट मंत्री था तो इस हलके के लिए ख़र्च किया गया एक भी पैसा गिनवाए। यहाँ तक कि वह खुद छह सालों से केंद्रीय मंत्री है जिसने कभी भी पंजाब की तरह इस हलके की खबर नहीं ली। उन्होंने कहा कि बादल परिवार ने तो कभी इस हलके का दौरा भी नहीं किया जबकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने तो डेरा बाबा नानक में कैबिनेट मीटिंग बुलाकर अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण दिया।

बादलों की बहु पर संकुचित राजसी हितों के लिए धार्मिक स्थानों पर प्रकाश पर्व समागमों पर राजनीति करने का लगाया दोष

उन्होंने कहा कि इससे पहले बादलों ने तो कभी डेरा बाबा नानक आकर ऐतिहासिक स्थान पर माथा भी नहीं टेका और न ही करतारपुर गलियारा खोलने की माँग की। यहाँ तक कि गलियारा खुलवाने के लिए लगातार यत्नशील रहे जत्थेदार कुलदीप सिंह वडाला को बादलों ने उस समय कमरे में बंद करवा दिया था जब वह समकालीन राष्ट्रपति को मिलने के लिए आए थे। अब राज्य सरकार द्वारा डेरा बाबा नानक से करतारपुर रास्ते की तरफ जाती सड़क का नाम भी जत्थेदार कुलदीप सिंह वडाला के नाम पर रखा जा रहा है। स. रंधावा ने डेरा बाबा नानक हलके के सर्वपक्षीय विकास के लिए बनाए प्रोजेक्टों का जिक्र करते हुए कहा कि डेरा बाबा नानक विकास अथॉरिटी बनाकर राज्य सरकार इस हलके की कायाकल्प कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर का सौंदर्यीकरण, सीचेवाल मॉडल पर सिवरेज सिस्टम का सुधार, हस्पताल का नवीनीकरण, सड़कीय ढांचे को चौड़ा और मज़बूत करना, शहर को विरासती रूप, पार्कों में एल.ई.डी. लाईटें, सोलर स्ट्रीट लाईटें, हवेली, बिजली के खंबों का नया रूप, पास के गाँवों के विकास आदि से हलके का रूप बदला जा रहा है। इसके अलावा इस हलके के एक और ऐतिहासिक कस्बे कलानौर को टूरिस्ट सर्किट अधीन लाया गया है और वहां डिग्री कॉलेज और गन्ना शोध केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। स. रंधावा ने कहा कि अकाली -भाजपा के 10 सालों के कुशासन के दौरान डेरा बाबा नानक हलका विकास को तरसता रहा, तब तो हरसिमरत बादल को यह हलका याद नहीं आया। आज जब करोड़ों नानक नाम लेवा संगत की अरदास के साथ रास्ता खुलने जा रहा है और डेरा बाबा नानक हलके का सर्वपक्षीय विकास हो रहा है तो अब वह राजनैतिक रोटियाँ सेकने के लिए मग्गरमच्छ के आंसु बहा रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सलाह दी कि आगे से यदि यहाँ आना हो तो वह नम्र सिख के तौर पर आए और गुरू घर में अपनी श्रद्धा भेंट करे न कि राजनीति करने आए। बादल दल अपनी खोई हुई राजसी शान को बहाल करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है जिसके लिए वह शिरोमणी कमेटी को अपने संकुचित राजनैतिक हितों की खातिर इस्तेमाल कर रहा है और श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व समागमों का सियासीकरण करने में लगा हुआ है।

सुखबीर बादल अपने संकुचित राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए सिख संगत को गुमराह करने से गुरेज़ करे-तृप्त बाजवा

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

● दसवीं पातशाही का 350वां प्रकाश पर्व बिहार सरकार ने ही मनाया था

● पंजाब सरकार और शिरोमणी कमेटी के बीच बादल परिवार ही सबसे बड़ी रुकावट

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तृप्त रजिन्दर सिंह बाजवा ने आज कहा कि सुखबीर बादल के इस बयान में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि जनवरी 2017 में पटना साहिब में मनाए गए श्री गुरु गोबिन्द सिंह के 350वें प्रकाश पर्व का मुख्य समागम शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मनाया गया था।

उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को कहा है कि वह श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर अपने परिवार की नेतागिरी कायम करने की लालसा में सिख संगत को गुमराह करने से गुरेज़ करें।

श्री बाजवा ने आज यहाँ एक लिखित प्रैस बयान में कहा है कि पटना साहिब में मनाए गए श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर करवाया गया मुख्य समागम वहाँ के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार द्वारा मनाया गया था।

उन्होंने कहा कि इस समागम में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी, बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविन्द, बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार, पंजाब के समकालीन मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने संगत को संबोधन किया था और शिरामणि कमेटी के प्रधान ने महज़ संगतों का धन्यवाद किया था।

उन्होंने कहा कि इस मुख्य समागम का संचालन बिहार सरकार की तरफ से पंजाबी यूनिवर्सिटी के उस समय के उप कुलपति डॉ. जसपाल सिंह को सौंपा गया था।

पंचायत मंत्री ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को इस संबंधी सब कुछ अच्छी तरह मालूम है क्योंकि वह उस समय स्टेज के सामने अपनी पत्नी और उस समय की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सहित संगत में बैठे थे। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल इस धार्मिक और बहुत ही नाज़ुक मामले बारे इसलिए झूठ बोल रहे हैं ताकि अगले महीने मनाए जा रहे बाब नानक के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर होने वाले ऐतिहासिक समागम में शिरोमणी कमेटी के द्वारा अपने परिवार की नेतागीरी कायम कर सकें।

श्री बाजवा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को यह याद होना चाहिए कि 1999 में मनायी गई खालसा पंथ की तीसरी शताब्दी भी पंजाब सरकार ने ही मनायी थी और 2007 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का 300वां गुरगद्दी दिवस नांदेड़ साहिब में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मनाया गया था। पंचायत मंत्री ने कहा कि 1999 में तीसरी खालसा जन्म शताब्दी के समागमों में अपनी नेतागीरी स्थापित करने के लिए ही बादल परिवार ने श्री अकाल तख़्त साहिब के हुक्मनामे का उल्लंघन करके पहले जत्थेदार गुरचरण सिंह टौहड़ा को पद से उतारा और फिर भाई रणजीत सिंह को अकाल तख़्त साहिब की जत्थेदारी से एक तरफ किया।

उन्होंने सुखबीर बादल को याद करवाया कि सिख पंथ के सिद्धांतों और परंपराओं का घोर उल्लंघन करने के कारण ही उनको इस समागम से कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार का मुँह देखना पड़ा था। इस चुनाव में सुखबीर सिंह बादल सहित शिरोमणी अकाली दल के एक उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवार हार गए थे।

श्री बाजवा ने कहा कि पंजाब सरकार और शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का यह ऐतिहासिक पर्व साझे तौर पर मनाने में सबसे बड़ी रुकावट बादल परिवार ही है जो अपने संकुचित राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए बहुत बेशर्मी से शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी माली और मानवीय साधन इस्तेमाल कर रहा है।

पंजाब सरकार श्री अकाल तख़्त साहिब की भावना के अनुसार यह ऐतिहासिक गुरूपर्व शिरोमणी कमेटी के साथ मिलकर मनाना चाहती है, परन्तु यह तब ही संभव होगा यदि शिरोमणी कमेटी के मौजूदा प्रधान और अन्य अधिकारी खालसा पंथ की इस महान संस्था को बादल परिवार के चंगुल में से निकाल कर सिख जगत की भावनाओं के अनुसार चलाएं।

ब्रह्म मोहिन्द्रा द्वारा स्थानीय निकाय विभाग की 12 कनाल जमीन स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त देने के लिए मंजूरी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

सद्भावना का एक नया उदाहरण पेश करते हुए श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने स्वास्थ्य विभाग को स्थानीय विभाग विभाग की 12 कनाल ज़मीन ज़िला मोगा के गाँव दूने के में 50 बिस्तरों का हस्पताल और ट्रौमा सैंटर बनाने के लिए बिल्कुल मुफ्त देने के लिए मंजूरी दे दी है। यह फ़ैसला राज्य के पिछड़े इलाके को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के मद्देनज़र किया गया है।

यह जानकारी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने दी। प्रवक्ता ने बताया कि लोक हितों की अहमीयत को ध्यान में रखते हुए इस पिछड़े इलाके को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्री ने जी.टी. रोड के साथ लगती यह अहम ज़मीन स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त देने का फैसला किया है। इस मुद्दे संबंधी अधिक जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि हस्पताल और ट्रौमा सैंटर के निर्माण के लिए

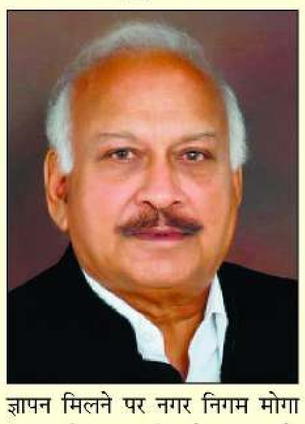

ज्ञापन मिलने पर नगर निगम मोगा द्वारा अपेक्षित ज़मीन के चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने गाँव दूने के में 12 कनाल का एक भूखंड चुना था जिसमें से 5 कनाल ज़मीन में 50 बिस्तरों का आयुष हस्पताल बनाने और बाकी 7 सात कनाल में ट्रौमा सैंटर बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि इससे पहले नगर निगम मोगा ने नगर निगम अधिनियम, 1976 का पालन करते हुए इस ज़मीन को कुलैक्टर रेट पर बेचने का प्रस्ताव पेश किया था।

जिला मोगा के गाँव दूने के में इस जगह पर बनाया जायेगा 50 बिस्तरों वाला हस्पताल और ट्रौमा सैंटर

प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद मोगा के विधायक डॉ. हरजोत कंवल ने स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा से मुलाकात की और मंत्री को इलाके में हस्पताल और ट्रौमा सैंटर की अत्यावश्यकता से अवगत करवाया।

उन्होंने मंत्री को यह अपेक्षित ज़मीन मुफ्त देने के लिए विनती की थी। मंत्री ने पिछड़े इलाके के लोगों को बढ़िया दर्जे की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाने के मद्देनज़र इस माँग को स्वीकार कर लिया और यह महत्वपूर्ण ज़मीन स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल मुफ्त देने सम्बन्धी हुक्म के दिए।

महाअष्टमी पर टीम इंडिया का महाविजय

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

द.अफ्रीका को 203 रन से दी मात

भारत ने पहले क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन दक्षिण अफ्रीका को 203 रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच के आखिरी दिन भारत को दिन के लिए साउथ अफ्रीका के 9 विकेट चटकाने थे। जिस काम को भारतीय गेंदबाजों ने बखूबी अंजाम दिया। दूसरी पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 35 रन देकर 5 विकेट लिए वहीं रवींद्र जडेजा ने 87 रन देकर 4 खिलाड़ियों को किया चलता।

मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा के घातक स्पेल ने अफ्रीकी टीम के एक के बाद 7 बल्लेबाजों को पविलियन भेजा, जबकि अंतिम दो विकेट झटकने के लिए भारत ने दूसरे सत्र में 22 ओवर और गेंदबाजी कर यह मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच में 8 विकेट झटकने वाले रविचंद्रन अश्विन ने मुथैया मुरलीधरन के सबसे तेज 350 विकेट लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की।

आर.बी.आई.दिसंबर माह में फिर कर सकता है रेपो रेट में कटौती

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर की द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा में भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि दिसंबर में केंद्रीय बैंक रेपो दर में चौथाई प्रतिशत की और कटौती करेगा। उसके बाद वह कटौती का सिलसिला रोक देगा।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह वृद्धि को प्रोत्साहन देने तक इस नरम रुख को जारी रखेगा। गोल्डमैन सैश ने एक रिपोर्ट में कहा कि हमें इस बात की काफी संभावना दिख रही है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को चौथाई प्रतिशत और घटाकर 4.90 प्रतिशत पर लाएगी। यह अक्टूबर में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में अतिरिक्त कटौती के हमारे अनुमान से मेल खाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक नीतिगत दर में कटौती के सिलसिले को रोकेगा क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के करीब रहेगी, जिससे दरों में और कटौती की गुंजाइश नहीं बनेगी। उसके बाद मौद्रिक नीति समिति देखेगी कि मौद्रिक रुख में नरमी का क्या असर हुआ है। साथ ही सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा है।